Ephedrin HCL Tabs, Cloxacillin Sodidum, Amoxycillin Trihydrate, Potassium Iodide, Sodium Iodide and

6 A.P.A.

जल-स्तर

2058. **डा० अबरार अहमद खान:** क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि नीचे जा रहे पानी के स्तर को रोकने के लिये सरकार क्या कदम उठा रही है और आठवीं पंचवर्षीय योजनावधि के दौरान सरकार द्वारा कार्यान्वित की जाने वाली जल के वितरण संबंधी योजनायें क्या क्या हैं?

जल संसाधन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री मनुभाई कोटाड़िया) : भूजल विकास के नियंत्रण तथा विनियमन हेतु केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकारों को एक माडल विधेयक अपनाने हेतु परिचालित किया है । अत्यधिक समुपयोजन के क्षेत्रों में भूजल विकास के संस्थागत वित्त पोषण पर प्रतिबंध लगाये गये हैं। देश में भूजल स्तरों की गिरावट को रोकने के लिये अन्य उपायों में ये शामिल हैं : वनरोपण, कंटूर वन्ध, नाला वन्द करना (नाला प्लगिंग) परिस्रवर्ण टैंकों का निर्माण तथा नवीकरण करना, भूजल का कृत्रिम पुनर्भरण, उप-सतही भूजल बढ़ाने के बांध ।

इसके अलवा खेतों में जल के कुशल तथा किफायती वितरण के लिये कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम को 8वीं पंचवर्षीय योजना में भी जारी रखे जाने का प्रस्ताव है ।

इन्दिरा गांधी नहर

2059. **डा० अबरार अहमद खान:** क्या जल संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर के कब तक पूरा हो जाने की संभावना है और इस पर अभी तक कितनी धनराशि खर्च हो चुकी है और कितनी धनराशि खर्च होने की संभावना है ?

(ख) इस समय इससे कितनी भूमि की सिंचाई की जा रही है तथा इसके पूरा होने पर इससे कितनी भूमि की सिंचाई किये जाने की संभावना है ;

(ग) क्या यह रेगिस्तानी क्षेत्र के लोगों को पीने का पानी की समस्या को इस परियोजना के कार्यन्वयन द्वारा हल किया जा सकेगा ; और

(घ) क्या सरकार राजस्थान में रेतीली भूमि की सिंचाई एवं पेयजल की समस्या का स्थायी हल निकालने के लिये कोई योजना बना रही है ; यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

जल संसाधन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री मनुभाई कोटाडिया): (क) मुख्य लहर की संपूर्ण लम्बाई दिसम्बर 1986 तक पूरी हो गई थी। वितरण प्रणाली को शामिल करते हुये इंदिरा गांधी नहर परियोजना के चरण I तथा चरण II पर संभावित व्यय 31 मार्च, 1990 तक 723 करोड़ रुपये होगा । राज्य सरकार ने सूचित किया है कि निधियों के उपलब्ध होने पर परियोजना के दसवीं योजना तक पूरे होने की संभावना है और नहर कार्यों के लिये 1222 करोड़ रुपये की और राशि की आवश्यकता होगी ।

(ख) 5.65 लाख हेक्टेयर : पूर्ण विकास होने पर सिंचित क्षेत्र 13.88 लाख हेक्टेयर होगा ।

(ग) और (घ) रेगिस्तानी जिलों के भागों में परियोजना से पेयजल आपूर्ति तथा औद्योगिक प्रयोगों के लिये 34 घन मीटर प्रति सैंकड की व्यवस्था की गई है । 1.18 लाख हेक्टेयर कृषि योग्य कमान क्षेत्र को सिंचाई तथा पेयजल प्रदान करने के लिये पहले से निर्माणाधीन इन्दिरा गांधी नहर परियोजना के अलावा सिद्धमुख तथा नोहर परियोजनाओं की तकनीकी-आर्थिक रूप से केन्द्रीय जल

आयोग द्वारा स्वीकृत किया गया है। राज्य सरकार इंदिरा गांधी नहर परियोजना से पेयजल आपूर्ति के आवंटन को भी बढ़ाने पर विचार कर रही है। नर्मदा जल में राज्य का हिस्सा उपलब्ध होने पर स्थिति में और सुधार होगा।

Employees of Pepsico working in Punjab Agro-Pepsi Project

2030. SHRI SUBAS MOHANTY: Will the Minister of FOOD PROCESSING INDUSTRIES be pleased to state:

(a) how many employees of Pepsico, U.S.A. are at present employed in India for the Punjab Agro-Pepsi project; and

(b) out of these, how many are employed for agriculture and horticulture development, how many are for potato chips project and how many for soft drink project?

THE MINISTER OF TEXTILES WITH ADDITIONAL CHARGE OF THE MINISTRY OF FOOD PROCESSING INDUSTRIES (SHRI SHARAD YADAV): (a) M/s. Pepsi Food Pvt. Ltd. have indicated that two employees of Pepsico, USA, are employed by them, both as full time Directors.

(b) According to the information furnished by M/s. Pepsico Foods Private Limited both the employees referred to at (a) above are in charge of potato and grain based business operations and export business development.

Proposal from PHD Chamber of Commerce and Industry for Amendments of Guidelines issued by RBI

2061. SHRI SURESH KALMADI: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether Government have received any proposals from PHDCCI for amendment in the existing RBI guidelines in respect of term lending institutions for reviving the sick but potentially viable companies;

(b) if so, what are the details thereof; and

(c) what is Government's reaction thereto?

THE MINISTER OF FINANCE (PROF. MADHU DANDAVATE): (a) and (b) PHDCCI have *inter-alia* suggested for liberal reschedulement of past liabilities of sick units, reduction in the rates of interest and remission of outstanding interest liabilities.

(c) RBI has reported that there is no proposal to amend the existing guidelines issued by them in the matter of revival of sick/weak units. However, the problems of sick units and measures for their rehabilitation are kept under review on an on-going basis.

Cash Incentives on FOB value of Exports of Bulk Drugs

2062. SHRI SANTOSH KUMAR SAHU: Will the Minister of COMMERCE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Government are giving 15 per cent cash incentives on FOB value of exports of bulk drugs and finished medicines;

(b) whether it is also a fact that his Ministry are considering to allow incentives only on added value and not on FOB value as it is very high; and

(c) if so, what are the details thereof and by when such a decision is likely to be taken?

THE MINISTER OF COMMERCE AND TOURISM (SHRI ARUN KUMAR NEHRU): (a) to (c) Cash Compensatory Support (CCS) is allowed on a selective basis and is granted primarily with the objective of making the exported items competitive in the International market by compensating the Indian Exporters for the elements of unrefunded indirect taxes and duties paid on the physically incorporated in-